कच्छ विकास बोर्ड की स्थापना

5919. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सीमावर्ती और औद्योगिक रूप से पिछड़े कच्छ क्षेत्र के विकास के लिए "कच्छ विकास बोर्ड" स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने "कच्छ विकास बोर्ड" को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(घ) सरकार द्वारा बोर्ड को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) प्रस्तावित विकास बोर्ड की मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Percentage stake of equity allowed for big indurtries in small units

5920. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1434 given in the Rajya Sabha on the 3rd March, 1994 and state:

(a) the present percentage allowed for large scale units to hold up stake in small units;

(b) the policy framed by Government to allow import of raw materials;

(c) whether there is any proposal to extend Bank credit limits for SSI Units; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Govt. has allowed upto 24 per cent equity participation in small scale units by other industrial undertakings.

(b) The Export and Import Policy of the Ministry of Commerce governs the policy regime for import of raw materials. Most raw materials required by the industry are placed on the Open General Licence (OGL) and are freely importable except for a small negative|restricted list.

(c) and (d) RBI has issued instructions to all scheduled commercial banks that henceforth, village, tiny industries and other SSI units having aggregate fund based working capital credit requirements upto Rs. One crore from the banking system may be provided working capital limits computed on the basis of a minimum of 20 per cent of their projected annual turnover for new as well as existing units.

Budgetary support to sick PSUs

5921. SHRI B. K. HARIPRASAD: SHRI MATANG SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had taken a decision to phase out budgetary support to sick Public Units within three years and if so, when this three-year term expires; and

(b) whether Government have abandoned the logic of letting unviable PSUs close down and continuing doles to idle labour and if so, whether Government would seriously consider pumping such money into the National Renewal Fund and address the problem squarely?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) Government give budgetary support for sick PSEs in selected cases. Funds are also made available for VRS etc. on case by case basis. National Renewal Fund provides a safety net work for labour rendered surplus or requiring retraining in the context of modernisation and making the PSEs viable.

प्रबंधकीय और संगठनात्मक पुनर्गठन के माध्यम से उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार किया जाना

5922. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान प्रबन्धकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन के माध्यम से किन-किन उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार किया गया है ; और

(ख) इन उपक्रमों के कार्यकरण में किये गये इस प्रकार के सुधार से उन्हें कितना प्रतिशत लाभ हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) प्रबन्धकीय एवं संगठनात्मक पुनर्गठन के अतिरिक्त श्रम, मशीन एवं पूंजी की उत्पादकता, अवस्थापना सम्बन्धी सहायता आदि कई अन्य कारक भी हैं जो सरकारी उपक्रमों के बेहतर कार्यकरण एवं लाभ को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। चूंकि ये सारे कारक एक-दूसरे पर अत्यधिक आश्रित होते हैं, इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से यह बता पाना कठिन होगा कि सिर्फ प्रबन्धकीय एवं संगठनात्मक पुनर्गठन के कारण सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण एवं लाभ में किस सीमा तक सुधार हुआ है।

उपक्रमों के कार्यकरण में उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन के माध्यम से सुधार किया जाना

5923. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान किन-किन उपक्रमों के कार्यकरण में उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन के माध्यम से सुधार किया गया है ; और

(ख) इन उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार से इन्हें कितना प्रतिशत लाभ हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन के अतिरिक्त श्रम, मशीन एंव पूंजी की उत्पादकता, अवस्थापना सम्बन्धी सहायता आदि कई अन्य कारक भी हैं जो सरकारी उपक्रमों के बेहतर कार्यकरण एवं लाभ को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। चूंकि ये सारे कारक एक दूसरे पर अत्यधिक आश्रित होते है, इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से यह बता पाना कठिन होगा कि सिर्फ उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन के कारण सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण एवं लाभ में किस सीमा तक सुधार हुआ है।

उपक्रमों में नवीनतम प्रौद्योगिकी

5924. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन उपक्रमों के कार्यकरण में नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधार किया गया है ; और

(ख) इन उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी से कितना सुधार हुआ है ?